under examination and active consideration of the Government. One of these works is: Guntur-Macherla Conversion to Broad Gauge and Nadikude-Bibinagar—New broad gauge line. May I know whether the South Central Railway had submitted any scheme and if so what are the details of the scheme?

SHRI L. N. MISHRA: This does not relate to Maharashtra. I have explained in detail the position regarding the proposals received, surveys completed or going on. If the hon. Member goes through paras 41 and 42 of my Budget speech, he will find where that line stands.

SHRI S. B. GIRI: I ask whether the Railway Board has received from the South Central Railway any proposals regarding Guntur-Macherla line and if so what are the details of that scheme?

MR. SPEAKER: You are asking a specific question; try to remain on the main line.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: The hon. Minister has made a statement that this particular part of the work has been sanctioned because it is a drought-affected area. It is a good departure from the old policy that even though they are not in the regular plan they will be taken up because of the drought conditions and several other factors. May I know whether the hon. Minister has in mind any such works in other areas and, if so, whether he has received any proposal from the Andhra Pradesh Government?

MR. SPEAKER: It is beyond the scope of the main question.

SHRI RAJA KULKARNI: All this confusion has been created because of a statement made by the Chairman of the Railway Board.

MR. SPEAKER: Next question.

भाखड़ा परियोजना से बिजली की सप्लाई में कमी किया जाना

*107. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा बिजली परियोजना से होने वाली बिजली की सप्लाई में कमी कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन कारखानों को मुआवजा देने का है जिन्हे भाखड़ा से बिजली की सप्लाई में कमी किए जाने के फलस्वरूप हानि हुई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख). भाखड़ा नंगल से बिजली की सप्लाई, जो कि 10 दिसम्बर, 1972 तक औसतन 12.5 मिलियन यूनिट थी, को इसके बाद कम कर के औसतन 10.26 मिलियन यूनिट कर दिया गया है ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि इस बिजली की कमी का किन किन राज्यों पर असर पड़ा और जिन फैक्टरियों या कृषि के कामों पर असर पड़ा है उसकी कुल लागत कितनी आंकी जायेगी ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : बिजली की कमी का असर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, और दिल्ली में डेसू के ऊपर पड़ा है । इससे होने वाली हानि के बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता । . . . . (**व्यवधान**) . . . .

श्री ओंकार लाल बेरवा : क्यों नहीं बतलाया जा सकता ? एक डेढ़ महीना पहले हम प्रश्न देते हैं । हमने पुछा था कि कितनी कमी

आंकी जा सकती है, फैक्टरियों और किसान के काम में कितनी कमी हो गई तो उसका अन्दाजा तो बतला दो । दो पैसा है, इतना ही कह दो ।

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरा प्रश्न कीजिए ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : उसका उत्तर भी यही दे देंगे ।

मैं जानना चाहता हू कि इस कमी का जिम्मेदार कौन है और आइन्दा कमी न होने पाए उसके लिए क्या इलाज किया गया है या किया जायेगा ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : श्रीमान जी, इस कमी की जिम्मेदारी प्रकृति के ऊपर है । ... (**व्यवधान**) .... भाखड़ा डैम में पानी का लेविल 1680 फिट है लेकिन इस वर्ष केवल 1609 फीट पानी ही आ सका । इसलिए यह कहना कि कौन जिम्मेदार है तो सिवाय प्रकृति के कोई और जिम्मेदार हो नहीं सकता । अगर पानी होता तो कमी करने का कोई शौक नहीं था । ... (**व्यवधान**) ..

SHRI MUHAMMED KHUDA BUKHSH: May I know from the Government whether this cut in the supply of electricity will not drive the industrialists to resort to generation of power by themselves, which will result in less demand for power from the industry?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO): We are having power shortage and any industry which wants to set up power generation for its use is being allowed to do so.

DR. H. P. SHARMA: On the face of it, the curtailment of power appears to be very marginal, but when viewed against the fact that 24 out of 26 districts are under grave famine conditions—it is the Government's assessment, not mine—will Government assure this House that at least this power shortage will be made up by Madhya Pradesh supply and the functioning of no water supply scheme will be curtailed due to power shortage?

DR. K. L. RAO: It is true that shortage of power produced in Bhakra is not so alarming that it should have caused all this cut. But in these two years the load in Punjab and Haryana has gone up by about 24 per cent and so the shortage has become so much more marked that it is not possible for us to see how we can make up this shortage except by expediting projects like Bhatinda and Badarpur. These are the two projects which will be able to make up the shortage in the immediate future. About Satpura, it is very difficult to say because after all a very small quantity is produced in Madhya Pradesh and whatever power is being generated now is now used for Rajasthan. Rajasthan itself is about to make a cut in its own power supply.

DR. H. P. SHARMA: Will Government assure that no water supply scheme will be affected by the power shortage?

DR. K. L. RAO: The power for drinking water is never cut down. That is the case all over India.

श्री नवल किशोर शर्मा: मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि राजस्थान में भाखड़ा से जो पावर शार्टेज हुई है उसको पूरा करने के लिए कोटा का जो थर्मल पावर स्टेशन है क्या उसको जल्दी चालू करने की दिशा में कुछ कदम उठाये जायेंगे ? क्योंकि बहुत दिनों से हम सुनते आ रहे हैं कि कोटा थर्मल पावर स्टेशन अब प्रोडक्शन में जा रहा है, अब प्रोडक्शन में जा रहा है इसीलिए में माननीय मंत्री जी से इसके बारे में जानकारी करना चाहता हूं ।

DR. K. L. RAO: If the hon. member is referring to the additional thermal unit, the project report is yet to be received. If he is referred to the atomic power plant at Ranapratap Sagar, one unit has been installed and is now under commissioning. It is expected that in the next one or two months, the supply of power will start.

श्री हुकम चन्द कछवाय : माननीय मंत्री महोदय ने अभी अपने उत्तर में बतलाया कि सतपुड़ा में काफी बिजली कम हो रही है और उसके कारण जो कुछ मिलता है राजस्थान को हम बिजली देते हैं तो क्या मंत्री जी के ध्यान में यह है कि सतपुड़ा में आर्थिक संकट है और साधनों की जो आवश्यकता है उनकी कमी के कारण वहां पर बिजली कम पैदा होती है इसलिए क्या उनको पूरा करने के लिए कोई उपाय किये जा रहे हैं ?

DR. K. L. RAO: What I said was in the context of the demand, the power produced in Satpura is not very much. Satpura is producing quite a good amount of power. Actually it has a surplus of nearly 6 to 8 lakh units, but in the context of the demand, I said it is not very much.

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैंने पूछा था कि वहां पर जो आर्थिक संकट है और जो अन्य साधनों की कमी है उसके लिए जो आर्थिक सहायता चाहिए वह केन्द्रीय सरकार के द्वारा नहीं मिल रही है ।

अध्यक्ष महोदय : इनकी क्या आदत है । बार बार खड़े हो जाते हैं । हर एक बात में ऐसा ही कर रहे हैं ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय मैं ने यह कहा था कि वहां पर आर्थिक संकट है और साधनों की कमी है जिसके कारण बिजली कम हो रही है ।

श्री सतपाल कपूर : मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि यह जो कमी वाले इलाके हैं—पंजाब, हरयाणा, दिल्ली—भाखड़ा का जहां असर पड़ा है तो वहां की स्टेट गवर्नमेंटस ने पावर बढ़ाने के लिए जिन पावर प्रोजेक्ट्स के लिए रिक्वेस्ट की है उन प्रोजेक्ट्स को कब तक क्लियर कर दिया जावेगा ? क्या सरकार एटामिक एनर्जी प्लान्ट पंजाब में और हरियाणा में थर्मल पावर स्टेशन लगाने की बात सोच रही है । और कब तक क्लीयर किया जायेगा तथा सतपुड़ा से जो बिजली पंजाब को दी थी वह कब तक पंजाब को मिल जायेगी ?

DR. K. L. RAO: The atomic power station takes a much longer period for generation of power. It will take at least 10 years. The real remedy for making up the shortage in Punjab, Haryana and these areas is not an atomic power station, but to expedite the projects that are undertaken, both hydro and thermal power stations. Then, there will be enough power supply. As I said, an atomic plant will take a longer time. Already, one project has been sanctioned and that power will be distributed among these regions also. But we do not know whether it will really come up. It may take 10 years.

श्री प्रताप सिंह : मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का ध्यान इस तरफ़ गया है कि झील गोविन्द-सागर बड़ी तेजी से भरती जा रही है जिस की वजह से आने वाले समय में बिजली की पैदावार और भी कम होने का अंदेशा

है। क्या इस को रोकने के लिए कि यह जल्दी न भरे और पानी की सप्लाई बराबर जारी रहे हिमाचल प्रदेश की सरकार को और ज्यादा पैसा देने का विचार रखते हैं ताकि कैचमेंट एरिया की हिफाजत कर सकें और आगे होने वाली हानि से बचा सकें ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के बारे में है, और आप हिमाचल सरकार को पैसा देने की बात पूछने लगे, यह इस से कैसे मेल खाता है ?

श्री प्रताप सिंह : झील जब भर जायेगी, तो पानी की कमी हो जायगी जिस से बिजली पैदा नहीं होगी। इसलिए जब तक कैचमेंट एरिया की हिफाजत नहीं की जायगी तब तक काम नहीं चलेगा, और इस कमी के लिए पैसे की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय : बताइये कब देंगे पैसा इन को।

DR. K. L. RAO: The hon. Member is evidently thinking of the silting, that the silting will occur and the storage capacity of water will go down. But the silting does not come for many many years. The shortage of water is not due to the silting. It is due to the fact that the rains have not been in adequate manner. I agree with the hon. Member that we should take all the soil conservation measures to ensure that silting does not take place in a very accelerated manner. We are already doing it. The soil conservation is being done in the catchment area of the river.

Setting up a Committee to remove Power Crisis

*108. SHRI SAMAR GUHA: Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state:

(a) whether Government have set up any Committee to review the situation arising out of power crisis in the country;

(b) if not, whether Government have taken any other steps to assess the nature and extent of the current power crisis and its effect on industry; and

(c) if so, the outcome of the assessment made by the Committee or through other methods?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI BALGOVIND VERMA): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House

Statement

(a) and (b). In view of the situation arising out of power crisis in the country, a group of Ministers has been constituted to advise on the steps which need to be taken to bring about an urgent improvement in the power supply position. This Group consists of the Minister (Planning) (Deputy Chairman of the Planning Commission) as Chairman with Minister of Finance, Minister of Industrial Development, Minister of Steel and Mines, Minister of Railways and Minister of Irrigation and Power as Members.

The Minister, Irrigation and Power held detailed discussions with the Chief Ministers of the States in each Region and worked out urgent measures for improvement and mutual assistance. Minister, Irrigation and Power also convened a meeting of eminent power engineers in the country and availed of their advice in regard to the power crisis.

(c) Action is already in hand on an emergent basis. Experts in the field of power have been appointed as Consultants to suggest ways and means of improving the performance of existing power generating units and expediting the completion of power stations under execution; and their suggestions are being implemented. Adequate supplies of coal, oil and